ज्वाइंट फोरम आफ बी एस एन एल एसोसिएशंस एंड यूनियंस आफ एक्जीक्यूटिव्स एंड नान--एक्जीक्यूटिव्स
नई दिल्ली

जे एफ/ जी एल 12.06.2009

बी एस एन एल अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील

बी एस एन एल में आई.पी.ओ. (विनिवेशीकरण) को शिकस्त देने के लिए संघर्ष की तैयारियों में एकजुट हों।

यू.पी.ए. सरकार पुनः निर्वाचित होने के पश्चात् बी एस एन एल सहित कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने की योजना बना रही है। यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि भारतीय एवं विदेशी बड़े पूँजीपतियों को, सार्वजनिक उपक्रमों को, मिट्टी के मोल सौंपा जा सके, जिससे उनके मुनाफे में बेतहासा वृद्धि सुनिश्चित हो सके। विगत कार्यकाल से यूपीए सरकार द्वारा अनेक सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु ट्रेड यूनियनों के प्रतिरोध एवं वामपंथियों के सशक्त विरोध (वामपंथियों पर सरकार निर्भर थी) के चलते यूपीए सरकार इस दिशा में कामयाब नहीं हो पायी थी। वर्तमान में यूपीए सरकार को संसद में पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। सरकार चलाने के लिए वामपंथी ताकतों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अतः यूपीए सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेशीकरण की योजना को आगे बढ़ाना चाहती है।

सरकार की इसी नीति को अमलीजामा पहनाने की नियति से बी एस एन एल बोर्ड ने बी एस एन एल की 10% हिस्सा पूंजी आई पी ओ के जरिये विनिवेश हेतु प्रस्तावित किया है। ज्ञात हुआ है कि बी एस एन एल ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु डीओटी को प्रेषित किया है। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार संचार मंत्री श्री ए. राजा ने बी एस एन एल प्रबंधन को यूनियनों से चर्चा कर, उन्हें प्रस्तावित विनिवेशीकरण योजना से सहमत कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। प्रचार माध्यमों की प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार पूर्व में कर्मचारियों को 10 रु. प्रति शेयर की दर से 500 शेयर की पेशकश की गयी थी, जिसे कर्मचारियों ने ठुकरा दिया था। इस बार कर्मचारियों को ललचाने के लिए उसी दर पर अधिक शेयर बेचने की पेशकश की जायेगी, ताकि कर्मचारी विनिवेशीकरण की योजना को स्वीकार कर लें। मीडिया द्वारा यह भी प्रकाशित किया गया है कि कर्मचारियों में विनिवेशीकरण योजना की स्वीकार्यता के लिए वेतन पुनरीक्षण के दौरान अधिक वेतन एवं भत्ते, बेहतर पदोन्नति एवं अन्य लाभ मुहैया कराये जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट यह दर्शाती है कि यदि बी एस एन एल कर्मचारी विनिवेश स्वीकार कर लेते हैं तो बी एस एन एल को नवरत्न का दर्जा दे दिया जायेगा। अफवाह है कि विनिवेश से अर्जित राशि का उपयोग इस उद्देश्य के साथ-साथ बी एस एन एल के विकास के लिए किया जायेगा।

परन्तु हमें इस सच्चाई को भली-भांति समझ लेना चाहिए कि बी एस एन एल के विनिवेश से अर्जित राशि से एक पैसा भी बी एस एन एल को नहीं दिया जायेगा। पूरा का पूरा पैसा "राष्ट्रीय निवेश कोष" में जमा किया जायेगा और इस कोष का प्रबन्धन कोष प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा, जो अपने विशेषाधिकार के द्वारा इसका निवेश करेगा। इस कोष से प्राप्त आमदनी (कोष नहीं, बल्कि केवल इससे प्राप्त आमदनी) का भुगतान सरकार को किया जायेगा और सरकार इस आमदनी का उपयोग 75% सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में और 25% बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने में करेगी। इस प्रकार इस विनिवेश से एक पैसा भी बी एस एन एल के खाते में नहीं आने वाला है। तब विनिवेश से अर्जित धनराशि का कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और बी एस एन एल के विकास के लिए उपयोग करने का सवाल ही कहाँ से उठता है?

इसलिए यह स्पष्ट है कि इस विनिवेश के पीछे न तो कर्मचारियों का कल्याण छिपा है और न ही बी एस एन एल का विकास इसका एक मात्र उद्देश्य क्रमबद्ध तरीके से बी एस एन एल में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करना है। शुरुआत में 10% शेयर बेंचकर और बाद में और अधिक शेयर बेंचकर ताकि अंततः 51% शेयर बेंचा जा सके एवं भविष्य में किसी उपयुक्त अवसर पर इसका निजीकरण किया जा सके। यह आश्वासन कि 51% शेयर सरकार अपने पास रखेगी, एक छलावा मात्र है, इसका उद्देश्य कर्मचारियों एवं जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है।

यह तर्क सच्चाई से परे है कि बी एस एन एल के 10% शेयर बेचने पर उसका बाजार मूल्य उभरकर सामने आयेगा, इससे बी एस एन एल के विकास को गति मिलेगी, क्योंकि प्रबंधन बाजार में बी एस एन एल के शेयरों के अधिक मूल्य हासिल करने में प्रयत्नशील रहेगा। एम टी एन एल में विनिवेश उसके विकास में मददगार साबित नहीं हुआ और जैसे-जैसे विनिवेश का प्रतिशत बढ़ता गया, उसकी हालत बिगड़ती गयी।

कहा जाता है कि बी एस एन एल की परिसम्पत्तियों का मूल्य चार लाँख करोड़ रुपये है और उसका 10% बेचने पर सरकार को 40 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और इस राशि को सरकार द्वारा समाज के विकास हेतु खर्च किया जायेगा। बी एस एन एल की परिसम्पत्तियों की वास्तविक कीमत लगभग चालीस लाख करोड़ रुपये है, न कि चार लाख करोड़ रुपये।

बी एस एन एल की परिसम्पत्तियों की कीमत का कम आकलन किया गया है ताकि इसके शेयरों को विदेशी और बड़े देशी पूंजीपतियों को सस्ते दरों पर बेंचा जा सके। सच तो यह है कि इससे होन वाली आमदनी भारत सरकार को भी मिलने वाली नहीं है। इस राशि को ''राष्ट्रीय निवेश कोष'' में जमा किया जायेगा, जिसका कोष प्रबन्धकों द्वारा सट्टेबाजाराना उपयोग किया जायेगा, इसके जरिए कुछ आदमनी होने पर उसे भारत सरकार को भुगतान किया जायेगा। निष्कर्ष यही निकलता है कि विनिवेश पूर्णतः चन्द बड़े देशी या विदेशी पूंजीपतियों के हितों के लिए और इससे राष्ट्रीय हितों को भारी नुकसान।

यदि हमने बीएसएनएल के निजीकरण की प्रक्रिया के इस प्रथम कदम को नहीं रोका तो भविष्य में कदम दर कदम इसका निजीकरण कर दिया जायेगा और हमारी नौकरी व पेंशन खतरे में पड़ जायेगी। इसके अतिरिक्त एक बार बीएसएनएल एवं एमटीएनएल जैसी सरकारी सार्वजनिक कम्पनियों का वजूद खत्म होने पर, निजी संचार कम्पनियां संगठित होकर संचार सेवाओं की दरों में मनमानी तरीके से बढ़ोतरी करेंगी। राष्ट्रीय सम्पत्ति (बीएसएनएल) को औने-पौने दर पर बेचना और संचार सेवाओं का समूचा क्षेत्र निजी संचार कम्पनियों के हाथों में सौंपना, दोनों ही कदम राष्ट्र के हितों के खिलाफ हैं।

जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और अन्य विकसित देश वैश्विक मंदी के चलते तीव्र आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति में हमारी सरकार ने खुशी-खुशी एलान किया था कि इस संकट का प्रभाव भारत पर उतना नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल तत्व बहुत मजबूत है। अर्थव्यवस्था के ये मूल तत्व और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां और सेवाएं हैं। अतः व्यवहारिक रूप से यह प्रमाणित होता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत किया जाना आवश्यक है। इसके बावजूद यूपीए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने के लिए प्रयासरत है। यहां पर उल्लेखनीय है कि अमेरिका में आर्थिक संकट के चलते विश्व की सबसे बड़ी कम्पनियों में से एक एक जनरल मोटर्स दिवालिया हो गयी और अमेरिका सरकार को इस कम्पनी को बचाने के लिए इसके शेयर खरीदने का निर्णय लेना पड़ा। अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों ने निजी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। जब विश्वव्यापी रुझान निजी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण है, यूपीए सरकार सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की ओर क्यों कदम उठा रही है? निश्चय ही इसका एकमात्र उद्देश्य चंद बड़े विदेशी व देशी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है।

इस तर्क में कोई वैधता नहीं है कि बीएसएनएल एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि सामाजिक क्षेत्र योजना लागू करने के जरिये सामाजिक विकास के लिए खर्च की जाएगी। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेड यूनियनों ने वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से भेंटकर सामाजिक विकास हेतु संसाधन जुटाने के कई उपाय सुझाये हैं, यदि उन सुझावों पर अमल किया जाय तो आम आदमी पर बोझ डाले बगैर एवं सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का रास्ता अख्तियार किये बिना, संसाधन जुटाया जा सकता है। ट्रेड यूनियनों ने सुझाव दिया है कि स्विस बैंक में जमा काला धन भारत वापस लाया जाय, सम्पन्न तबकों पर कर लगाया जाय, धनवानों से बकाये कर की वसूली की जाय, बड़े उद्योग घरानों को दी गयी रियायतें समाप्त की जाय, इन कदमों के परिपालन पर देश के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त किया जा सकता है।

चूंकि यह विनिवेश कर्मचारियों, बीएसएनएल कम्पनी एवं राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, ज्वाइंट फोरम आफ बीएसएनएल एसोसिएशंस एण्ड यूनियन्स आफ एक्जीक्यूटिव एण्ड नान एक्जीक्यूटिव ने प्रस्तावित विनिवेश का पुरजोर विरोध करने एवं संघर्ष करने का निर्णय लिया है। उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकताबद्ध होकर विनिवेश के मुहिम को परास्त करने का आह्वान किया है। देशभक्त अवाम एवं राजनीतिक पार्टियां इस संघर्ष में हमारे समर्थन में खड़ी होंगी।

ज्वाइंट फोरम मांग करता है कि नौ करोड़ तीस लाख जीएसएम लाइनों के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया को अविलम्ब अन्तिम रूप दें ताकि बड़े पैमाने पर जीएसएम सेल फोन देने में बीएसएनएल सफल हो और प्रबन्ध बीएसएनएल के विकास के लिए आवश्यक कदम उठा सके। बीएसएनएल के विकास के लिए पर्याप्त संचित कोष मौजूद है और इसके बावजूद यदि धन की आवश्यकता है, बीएसएनएल के विकास हेतु बाजार से ऋण लिया जा सकता है। बीएसएनएल के पास कुशल मानव शक्ति है, विकास के लिए उपयुक्त रणनीति अपनाकर, प्रबन्धन द्वारा इस मानव शक्ति का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

अतः ज्वाइंट फोरम विनिवेश के प्रस्ताव को परास्त करने बीएसएनएल को सुरक्षित रखने एवं बीएसएनएल के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समस्त एक्जीक्यूटिव एवं नान-एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को एकताबद्ध होकर संघर्ष करने का आह्वान करता है।

गर्मजोश युक्त बिरादराना अभिवादन के साथ

V. A. N. Namboodiri

वी ए एन नंबूदिरी
संयोजक